पूर्ण बेंच

सिविल विविध

न्यायमूर्ति ओ चिन्नप्पा रेड्डी, एस सी मित्तल और सुरिंदर सिंह

के समक्ष।

जगदीश राय, आदि - याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य, आदि - *उत्तरदाता।*

1972 की सिविल रिट याचिका संख्या 2149।

17 सितंबर, 1976।

भारत का संविधान 1950 - *अनुच्छेद* 16 - *भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में पदों का आरक्षण - यदि अनुमेय हो।*

यह माना गया कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 (4) अनुच्छेद 16 (1) का अपवाद नहीं है, लेकिन समानता प्राप्त करने के तरीकों में से एक का चित्रण है। यह आवश्यक वर्गीकरणों का संपूर्ण नहीं है और इसलिए, समानता प्राप्त करने के लिए स्वीकार्य है और अनुच्छेद 14 के तहत स्थितियों पर लागू सामान्य सिद्धांत अनुच्छेद 16 (1) के तहत समान रूप से लागू होते हैं। जबकि राज्य के तहत नियुक्ति चाहने वालों में से सर्वश्रेष्ठ और सबसे मेधावी का चयन किया जाना चाहिए, यह भी उतना ही उचित और न्यायसंगत है कि पदों का एक उचित अनुपात उन लोगों को दिया जाना चाहिए, जो एक अजीब विकलांगता के कारण, उन लोगों के खिलाफ मौका नहीं दे सकते हैं जो इतने विकलांग नहीं हैं। यह अनुच्छेद 16(4) के सिद्धांत का उन लोगों के लिए विस्तार होगा जो अनुच्छेद 16(4) के तहत नहीं आते हैं। रक्षा कर्मी जो वर्षों से सेना, नौसेना और वायु सेना के साथ

अपनी सेवा के कारण सरकार में प्रवेश करने के अवसर खो चुके हैं।

जगदीश राय आदि बनाम हरियाणा राज्य, आदि (चिन्नप्पा रेड्डी, जे)

अनुशासन, बलिदान, सार्वजनिक कर्तव्य की भावना, पहल, वफादारी और नेतृत्व के गुणों के बावजूद, सेवा और सामान्य नागरिक जीवन के साथ संपर्क खो चुके हैं, नागरिक नौकरियों के लिए नागरिकों के साथ प्रतिस्पर्धा करना बेहद मुश्किल हो सकता है, जो उन्होंने निस्संदेह रक्षा बलों के सदस्यों के रूप में हासिल किया होगा। राज्य का निस्संदेह यह दायित्व है कि वह उन भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार प्रदान करे जिन्होंने देश की सुरक्षा के हितों की निष्ठापूर्वक सेवा की है और अपने जीवन को जोखिम में डालने के लिए तैयार हैं। राज्य का दायित्व है कि वह उन्हें नागरिक आवेदकों की प्रतिस्पर्धा से बचाए, जिनके खिलाफ उन्हें मौका नहीं मिल सकता है। इस प्रकार राज्य द्वारा उन्हें भर्ती के स्रोत के रूप में अलग से वर्गीकृत करना और उनके लिए पद आरक्षित करना उचित है।

(पैरा 7 और 10)

माननीय न्यायमूर्ति एस एस संधावालिया द्वारा मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए 4 दिसंबर, 1972 *को खंडपीठ को मामला सौंपा गया। माननीय न्यायमूर्ति एसएस संधावालिया और माननीय न्यायमूर्ति प्रेम चंद जैन की खंडपीठ ने अंतिम निर्णय के लिए* 16 *दिसंबर,* 1975 *को मामले को फिर से पूर्ण पीठ को भेज दिया। माननीय न्यायमूर्ति ओ चिन्नप्पा रेड्डी, माननीय न्यायमूर्ति एस सी मित्तल और माननीय न्यायमूर्ति सुरिंदर सिंह की पूर्ण पीठ ने अंततः 17 सितंबर, 1976 को मामले का फैसला किया।*

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 *के तहत याचिका में अनुरोध किया गया है कि मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित समझे जाने वाले किसी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश की प्रकृति में एक रिट, जिससे उक्त बोर्ड द्वारा किए गए पूरे चयन को रद्द कर दिया जाए और निदेशक द्वारा पारित याचिकाकर्ताओं की सेवाओं की समाप्ति के आदेश को बहुत विनम्रता से जारी किया जा सकता है और इस रिट याचिका की लागत हो सकती है। याचिकाकर्ताओं को भी सम्मानित किया जाए।*

और आगे प्रार्थना है कि इस रिट याचिका का अंतिम निपटान लंबित रहने तक, निदेशक (प्रतिवादी संख्या 2) *याचिकाकर्ताओं की सेवाओं की समाप्ति के आदेशों को लागू नहीं करने का निर्देश दिया जा सकता है।*

याचिकाकर्ताओं की ओर से न्यायमित्र के रूप में पी'एडवोकेट> जे-एल-गुप्ता' एडवोकेट।

Adv^ms f0r A' ग्राम- हरियाणा, सुरेश अंबा के साथ, अधिवक्ताओं, *उत्तरदाताओं के लिए।*

निर्णय

न्यायमूर्ति ओ चिन्नप्पा रेड्डी, -(1) इन दो रिट याचिकाओं में उप-निरीक्षकों के पदों में 28 प्रतिशत रिक्तियों का आरक्षण पूर्व सैनिकों के लिए खाद्य और आपूर्ति विभाग का अर्थ है कि सेना के जवानों को रिहा करना, संविधान के अनुच्छेद 16(1) के विपरीत सवाल उठाया जाता है। हमारे अनुरोध पर, श्री जवाहर लाल गुप्ता ने न्यायमित्र के रूप में मामले में बहस *की* और हम उनके द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए उनके आभारी हैं।

(दो) श्री जवाहर लाल गुप्ता ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 16(4) में

उल्लिखित सीमा को छोड़कर अनुच्छेद 16(3) और 16(4) पदों के किसी भी आरक्षण पर विचार नहीं करता है, कि अनुच्छेद 16(3) और 16(4) राज्य के तहत किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित

मामलों के संबंध में सभी अनुमेय वर्गीकरण का संपूर्ण है और अनुच्छेद 16(1) पदों की जरूरतों से संबंधित योग्यताओं को निर्धारित करने की अनुमति देता है, लेकिन पदों से संबंधित योग्यता नहीं। पदों पर नियुक्ति के लिए खुद को पेश करने वाले व्यक्तियों की आवश्यकताएं।

(तीन) प्रारंभ में, यह अच्छा है कि अतीत में मौलिक अधिकारों के महिमामंडन द्वारा उनके अनुमानित 'पारलौकिक' प्रकृति के कारण और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और संविधान के अन्य अनुच्छेदों के आलोक में मौलिक अधिकारों की व्याख्या करने में विफलता के कारण बनाए गए मकड़जाल से छुटकारा पाया जाए। क्योंकि निर्देशक सिद्धांत न्यायसंगत नहीं थे, जबकि मौलिक अधिकार थे, यह सोचा गया था कि मौलिक अधिकारों की तुलना में निर्देशक सिद्धांत द्वितीयक महत्व के थे। सोचने का यह तरीका अतीत का है। अब यह महसूस किया जाता है और बिना किसी विरोधाभास के दावा किया जाता है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का संविधान में मौलिक अधिकारों की तुलना में उच्च स्थान है, यदि उच्च नहीं है और उन्हें अनिवार्य रूप से मौलिक अधिकारों में पढ़ा जाना चाहिए। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर हमला किए गए कानून की अब यह पता लगाने के लिए जांच की जाती है कि क्या वे निर्देशक सिद्धांतों में से एक या दूसरे को आगे नहीं बढ़ाते हैं या यदि वे अपने

नागरिकों या उसके नागरिकों के वर्गों के प्रति संवैधानिक या अन्यथा राज्य के कुछ निस्संदेह दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। और यदि उन्हें उचित प्रतिबंध, अनुमेय वर्गीकरण आदि जैसे आधारों पर बनाए नहीं रखा जा सकता है। सोचने के पुराने तरीके का एक अवशेष यह विचार है कि अनुच्छेद 15 के खंड (4) और अनुच्छेद 16 के खंड (4) संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के अपवाद की प्रकृति में हैं। पुराने विचार ने अब इस विचार

को रास्ता दिया है कि अनुच्छेद 15 के खंड (4) और अनुच्छेद 16 के खंड (4) का उद्देश्य अनुच्छेद 14 और अन्य खंडों द्वारा घोषित और गारंटीकृत समानता को प्राप्त करना है।

अनुच्छेद 15 और 16 के अनुसार, *केरल राज्य* बनाम *एन एम इहोमास* (1) मुख्य न्यायमूर्ति रे ने कहा: -

> "अनुच्छेद 14 और 16 (1) के भीतर समानता के नियम का उल्लंघन एक नियम द्वारा नहीं किया जाएगा जो दक्षता की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के बाद गैर-प्रतिनिधित्व वाले वर्गों के लिए सेवाओं में प्रतिनिधित्व की समानता सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 16(1) के तहत सेवाओं में अवसर की समानता के लिए सभी वैध तरीके उपलब्ध हैं, अनुच्छेद 16 (4) *अनुच्छेद* 16(1) *में सन्निहित समानता प्राप्त करने के तरीकों में से एक को इंगित करता* है।

इसी मामले में न्यायमूर्ति मैथ्यू ने कहा:-

> "मैं मानता हूं कि अनुच्छेद 16(4) अनुच्छेद 16(1) के अपवाद के रूप में व्याख्या करने में सक्षम है यदि अनुच्छेद 16(1) में कल्पना की गई अवसर की समानता एक बाँझ है, जो संख्यात्मक समानता की अवधारणा के लिए तैयार है जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक पृष्ठभूमि का कोई ध्यान नहीं रखता है। यदि अनुच्छेद 16(1) के तहत गारंटीकृत अवसर की समानता का अर्थ प्रभावी भौतिक समानता है, *तो*

अनुच्छेद 16(4), *यह अनुच्छेद 16(1)* का अपवाद नहीं है*। यह केवल यह बताने का एक जोरदार तरीका है कि वह किस हद तक अवसर की समानता को ले जा सकते* हैं, अर्थात्, आरक्षण बनाने के बिंदु तक भी अनुच्छेद 16 (1) सभी क्षेत्रों में समानता सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक योजना का एक हिस्सा है। यह अनुच्छेद 14 और 15 में सन्निहित कानून के तहत समानता की बड़ी अवधारणा के आवेदन का एक उदाहरण है। अनुच्छेद 16(1) अनुच्छेद 14 की तरह वर्गीकरण की अनुमति देता है।

न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने कहा: -

यह सच है कि यह कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 16(4) एक अपवाद है, लेकिन, बारीकी से जांच की गई, यह *संवैधानिक पवित्र वर्गीकरण का एक उदाहरण है* । इस प्रकार मूल प्रश्न अनुच्छेद 16(1) में लागू सामाजिक गतिशीलता में से एक है। मेरा निष्कर्ष यह है कि अनुच्छेद 14 से 16 की प्रतिभा शाब्दिक समानता में नहीं बल्कि स्पष्ट असमानता के प्रगतिशील उन्मूलन में निहित है।

न्यायमूर्ति फजल अली ने कहा: -

यह सच है कि इस न्यायालय के कुछ प्राधिकारी हैं कि खंड (4) अनुच्छेद 16(1) का अपवाद है, लेकिन उचित सम्मान के साथ मैं इस विचार को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं।

जे एगुइश रियाई, आदि। *v.* बासी ओई-इयाना, आदि (। चिन्नप्पा रेड्डी, जे।

(1) 1976 (1) एसएलआर 805।

(चार) केरल राज्य *बनाम* एनएम थॉमस *मामले में* उच्चतम न्यायालय ने केरल सरकार के एक नियम और दो आदेशों की वैधता के प्रश्न पर विचार किया जिसके द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को पदोन्नति के लिए आवश्यक निर्धारित कतिपय परीक्षाओं को पास करने से अस्थायी छूट प्रदान की गई थी। इस नियम पर सवाल उठाने वालों द्वारा यह तर्क दिया गया था कि अनुच्छेद 16(4) अनुच्छेद 16(1) के तहत सभी अनुमेय वर्गीकरणो से संपूर्ण है और इसलिए, अनुच्छेद 16(4) द्वारा विचार किए गए पदों के आरक्षण के अलावा, अनुच्छेद 16(1) द्वारा गारंटीकृत अधिकार में कोई अन्य कटौती नहीं हो सकती है। यह कहा गया था कि अनुच्छेद 14 के तहत उत्पन्न होने वाले मामलों में अनुमेय वर्गीकरण से संबंधित सामान्य सिद्धांतों का अनुच्छेद 16 के तहत उत्पन्न होने वाले मामलों पर कोई लागू नहीं होता है। इन दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। मुख्य न्यायमूर्ति रे, ने देखा: -

> "अनुच्छेद 14, 15 और 16 संवैधानिक गारंटीकृत अधिकारों की एक श्रृंखला का हिस्सा हैं। ये अधिकार एक-दूसरे के पूरक हैं। अनुच्छेद 16 जो रोजगार से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों को अवसर की समानता सुनिश्चित करता है, अनुच्छेद 14 में निहित समानता की गारंटी की एक घटना है। अनुच्छेद 16(1) अनुच्छेद 14 को प्रभावी बनाता है। अनुच्छेद 14 और 16(1) दोनों प्राप्त की जाने वाली वस्तुओं के साथ संबंध रखने वाले उचित वर्गीकरण की अनुमति देते हैं। अनुच्छेद 16 के तहत रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में कर्मचारियों का उचित वर्गीकरण हो सकता है।

(पाँच) पदोन्नति के मामले में अनुच्छेद 16 (1) के तहत अनुमेय वर्गीकरण को स्पष्ट करने के लिए, मुख्य न्यायमूर्ति रे, ने *गोविंद दत्तात्रेय केलकर* बनाम मुख्य आयात नियंत्रक *(2),* गंगा राम *बनाम भारत संघ (3), रोशन लाल टंडन बनाम भारत संघ* (4), *और जम्मू और कश्मीर राज्य* बनाम *त्रिलोकी नाथ खोसा* (5) का उल्लेख किया। बाद में, विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की: -

> "अनुच्छेद 16 (1) के तहत सेवाओं में अवसर की समानता के लिए सभी वैध तरीके उपलब्ध हैं। अनुच्छेद 16 (1) क्या है? सकारात्मक जबकि अनुच्छेद 14 भाषा में नकारात्मक है। अनुच्छेद 16(4) अनुच्छेद 16(1) में सन्निहित समानता प्राप्त करने के तरीकों में से एक को इंगित करता है। अनुच्छेद 16(1) "समानता" शब्द का उपयोग करते हुए इसे पदोन्नति और समाप्ति के माध्यम से नियुक्ति से लेकर पेंशन और ग्रेच्युटी के भुगतान तक रोजगार के सभी मामलों से संबंधित बनाता है। अनुच्छेद 16(1) अनुच्छेद 16(2) द्वारा निषिद्ध भेदभाव से जुड़े वर्गीकरण को छोड़कर कानून या राज्य कार्रवाई के उद्देश्य और उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण की अनुमति देता है।

(2) (1967) 2 एस.सी.आर. 29.

(3) (1970) 1 एस.सी.आर. 377.

(4) (1968) 1 एस.सी.आर. 185.

(5) (1974) 1 एस.सी.आर. 771.

कानूनों के समान संरक्षण में आवश्यक रूप से वर्गीकरण शामिल है। वर्गीकरण की वैधता को कानून के उद्देश्य के संदर्भ में समायोजित किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में वर्गीकरण उचित है क्योंकि वर्गीकरण का उद्देश्य अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों को एक सीमित सीमा तक पदोन्नति द्वारा प्रतिनिधित्व पाने में सक्षम बनाना है। समय के दृष्टिकोण से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों को दक्षता के अनुरूप समानता देने के उद्देश्य से एक अलग व्यवहार दिया जाता है।

न्यायमूर्ति मैथ्यू ने इस स्थिति को दोहराया कि अनुच्छेद 16(1) सभी क्षेत्रों में समानता सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक योजना का केवल एक हिस्सा था, कि यह अनुच्छेद 14 और 15 में सन्निहित कानून के तहत समानता की बड़ी अवधारणा के आवेदन का एक उदाहरण था और यह अनुच्छेद 14 की तरह वर्गीकरण की अनुमति देता था। उन्होंने *जय सिंघानी बनाम भारत संघ* (6), *मैसूर राज्य बनाम* पी *नरसिंग राव* (7) और सीए *राजेंद्रन* बनाम *भारत संघ (8) का उल्लेख किया,* जहां सुप्रीम कोर्ट ने पहले घोषणा की थी कि अनुच्छेद 14 और 16 एक-दूसरे के पूरक संवैधानिक गारंटी की एक ही संहिता का हिस्सा हैं, कि अनुच्छेद 16(1) अनुच्छेद 14 में निर्धारित समानता के सामान्य नियम के आवेदन का एक उदाहरण था। और यह कि इसे इस तरह से माना जाना चाहिए।

(6) (1967) 2 एस.सी.आर.

(7) (1968) 1 एस.सी.आर.

जगदीश राय आदि। ***(v)*** हरियाणा राज्य, आदि (चिन्नप्पा रेड्डी, जे)

(8) (1968) 1 एस.सी.आर

न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने कहा: -

उन्होंने कहा, "समान अवसर एक उम्मीद है, खतरा नहीं। यदि अनुच्छेद 14 उचित वर्गीकरण को स्वीकार करता है, तो अनुच्छेद 16(1) और इस न्यायालय ने भी ऐसा कहा था। वर्तमान मामले में, आर्थिक उन्नति और घोर दावों को बढ़ावा देना कम प्रतिनिधित्व वाले और दयनीय रूप से उपेक्षित वर्ग, जिन्हें अन्यथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के रूप में वर्णित किया गया है, प्रशासनिक दक्षता के रखरखाव के साथ, अनुच्छेद 46 और 335 द्वारा संवैधानिक रूप से स्वीकृत और अनुच्छेद 16(1) में यथोचित रूप से समायोजित उद्देश्य है। हरिजनों का निराशाजनक सामाजिक परिवेश अंतर, इतने जोर-शोर से अस्पष्ट है। निश्चित रूप से इसका ऊपर निर्धारित वस्तु से तर्कसंगत संबंध है"।

(छः) केरल राज्य *बनाम* एनएम थॉमस *मामले में दिए गए फैसले* ने उस पुरानी बाँझपन से छुटकारा पा लिया है, जिसके बारे में न्यायमूर्ति मैथ्यू, न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति फजल अली ने संकेत दिया था और समानता और विशेष रूप से अवसर की समानता की अवधारणा में एक नई गतिशीलता और एक नया आयाम पेश किया है। कहा जा सकता है कि संविधान के समानता खंडों की व्याख्या में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। समानता प्राप्त करने के उद्देश्य से कानूनों को अनुमेय अपवादों के रूप में 'क्षमायाचना' की व्याख्या करना अब आवश्यक नहीं है। अब साहसपूर्वक दावा किया जा सकता है कि ऐसे कानून समानता की आवश्यक घटनाएं हैं।

(सात) कानूनी स्थिति, जैसा कि *केरल राज्य* बनाम *एनएम थॉमस* में समझाया गया है, को अब तय किया जा सकता है, कि अनुच्छेद 16(4) अनुच्छेद 16(1) का अपवाद नहीं है, बल्कि समानता प्राप्त करने के तरीकों में से एक का उदाहरण है, कि यह आवश्यक वर्गीकरणो में से संपूर्ण नहीं है और इसलिए, समानता प्राप्त करने के लिए स्वीकार्य है और यह कि अनुच्छेद 14 के तहत स्थितियों पर लागू सामान्य सिद्धांत अनुच्छेद 16 के तहत समान रूप से लागू होते हैं। यह याचिकाकर्ताओं की ओर से की गई प्रमुख प्रस्तुतियों का पूरी तरह से जवाब देता है।

(आठ) अभी भी यह सवाल बना हुआ है कि क्या पूर्व सैनिकों के लिए पदों का आरक्षण अनुच्छेद 16(1) के भीतर एक वर्गीकरण है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील का शीट-एंकर सुखा-नंदन ठाकुर बनाम बिहार राज्य (9) था। अहमद और रामास्वामी जस्टिस ने विचार किया कि अनुच्छेद 16(4) अनुच्छेद 16(1) द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार के अपवाद की प्रकृति में था, कि संविधान के निर्माताओं ने अनुच्छेद 16(1) के लिए किसी अन्य अपवाद का इरादा नहीं किया था और छंटनी के मामले में विस्थापित व्यक्तियों और राजनीतिक पीड़ितों को दिखाई गई विशेष रियायत अनुच्छेद 16(1) के साथ असंगत थी। न्यायमूर्ति रामास्वामी ने यह भी कहा कि उन्हें यह समझने में मुश्किल होती है कि एक उम्मीदवार के 'राजनीतिक पीड़ित' या 'विस्थापित व्यक्ति' होने की परिस्थितियों का कोई भौतिक संबंध कैसे था।

(9) ए.आई.आर. 1957 पटना 617.

या आपूर्ति निरीक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों की दक्षता या उचित प्रदर्शन पर असर डालना। मुख्य न्यायाधीश सिन्हा, जो अल्पमत में थे, ने विचार व्यक्त किया कि दक्षता राज्य के रोजगार का एकमात्र उद्देश्य नहीं था। यह अन्य उद्देश्यों के लिए भी हो सकता है। यह संविधान के अनुच्छेद 39, 41, 46 आदि में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए हो सकता है। विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने कहा:-

> पीठ ने कहा, "हमारे समक्ष यह विवादित नहीं था कि विभाजन के बाद की परिस्थितियों और उसके बाद की घटनाओं के कारण विस्थापित लोगों को अवांछित अभाव का सामना करना पड़ा और हम निश्चित रूप से उन परिस्थितियों का न्यायिक संज्ञान ले सकते हैं। इसी प्रकार, जैसा कि ऊपर बताया गया है, राजनीतिक पीड़ित अवांछित अभाव का एक और उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और मुझे कोई विशेष कारण नहीं दिखता है कि राज्य सरकार ऐसे व्यक्तियों का अलग वर्गीकरण क्यों नहीं कर सकती है ताकि उन्हें राज्य के तहत रोजगार में रोजगार या वरीयता दी जा सके। लेकिन विस्थापित व्यक्तियों और राजनीतिक पीड़ितों के मामले अवांछित अभाव के मामले हैं, और, मेरी राय में, राज्य सरकार उन्हें राज्य सरकार के माध्यम से सार्वजनिक सहायता देने के लिए वर्गीकृत कर सकती है। इस तरह का वर्गीकरण न तो अनुचित है और न ही यह कहा जा सकता है कि इसका उस उद्देश्य या उद्देश्य से कोई संबंध नहीं है जिसके लिए राज्य रोजगार किया गया है।

(नौ) विद्वान मुख्य न्यायाधीश द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के

पक्ष में कहने के लिए बहुत कुछ है। यह केरल राज्य बनाम एन एम थॉमस, जिसे पहले ही उद्धृत किया जा चुका है और चंचला बनाम मैसूर राज्य (10) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के अनुरूप है। इस मोड़ पर बाद के निर्णय का उल्लेख करना उपयोगी होगा। हालांकि यह एक ऐसा मामला था जहां अनुच्छेद 14 और 15 पर विचार किया गया था, न कि अनुच्छेद 16, यह इसमें शामिल सिद्धांतों पर काफी प्रकाश डालता है। विचार किए गए प्रश्नों में से एक प्रश्न राजनीतिक पीड़ितों, रक्षा कामकों और भूतपूर्व रक्षा कामकों के बच्चों के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटों की एक निश्चित संख्या निर्धारित करने की वैधता के बारे में था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा कि यह आरक्षण का मामला नहीं है, बल्कि चयन के लिए स्रोत निर्धारित करने का मामला है, जो देश की सुरक्षा और इसी तरह के हितों की सेवा करने वालों के प्रति दायित्वों जैसे कुछ अतिरंजित विचारों के कारण आवश्यक है। इस बात पर विचार करने के लिए कार्यवाही करते हुए कि क्या चयन के लिए स्रोत के रूप में राजनीतिक पीड़ितों, रक्षा और पूर्व रक्षा कर्मियों के बच्चों के वर्गीकरण का उस उद्देश्य से उचित संबंध था जिसके लिए प्रवेश के नियम बनाए गए थे, विद्वान न्यायाधीशों ने कहा: -

> "प्रवेश के नियमों का उद्देश्य स्पष्ट रूप से प्रवेश चाहने वालों के बीच सीटों का उचित और न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना हो सकता है और जो विश्वविद्यालय विनियमों के तहत पात्र हैं। इस तरह का वितरण इस सिद्धांत पर हो सकता है कि प्रवेश सर्वश्रेष्ठ और सबसे मेधावी के लिए उपलब्ध होना चाहिए

जगदीश राय आदि। *(v)* हरियाणा राज्य, आदि (चिन्नप्पा रेड्डी, जे)

(10) 1971 एस.सी. 176

जगदीश काई, आदि। *(v)* बासी और हरियाणा, आदि चिन्नप्पा केड्डी, जे।

लेकिन एक समान रूप से निष्पक्ष और न्यायसंगत सिद्धांत वह भी होगा जो विकलांग लोगों के उचित अनुपात में प्रवेश सुनिश्चित करता है, लेकिन उन्हें दिए गए अधिमान्य उपचार के लिए, उन लोगों के खिलाफ कोई मौका नहीं देगा जो इतने विकलांग नहीं हैं और इसलिए, एक बेहतर स्थिति में हैं। अनुच्छेद 15(4) में अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि अधिमान्य रूप से अधिमान्य व्यवहार किया जा सकता है क्योंकि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को इसकी आवश्यकता है, ताकि समय के साथ वे समाज के अधिक उन्नत वर्गों के साथ समान स्थिति में खड़े हों। यह किसी भी तरह से अनुचित नहीं होगा यदि उस सिद्धांत को उन लोगों पर भी लागू किया जाए जो विकलांग हैं लेकिन अनुच्छेद 15(4) के तहत नहीं आते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि रक्षा कामकों और भूतपूर्व रक्षा कामकों के बच्चों के लिए आरक्षण को बरकरार रखा गया है। इस तरह के आरक्षण का मानदंड यह है कि रक्षा बलों में सेवारत या जिन्होंने इस तरह सेवा की थी, वे अपने बच्चों को शिक्षा देने में नुकसान में थे क्योंकि उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, कठिन स्थानों पर रहना पड़ता था, जहां सामान्य रूप से कहीं और उपलब्ध सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। हमारे विचार में उस सिद्धांत को राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों तक विस्तारित करना अनुचित नहीं है, जो मुक्ति संघर्ष में उनकी भागीदारी के परिणामस्वरूप जीवन में अस्थिर हो गए; कुछ मामलों में आर्थिक रूप से बर्बाद हो गए, और इसलिए, वे अपने बच्चों को शिक्षा का वह वर्ग उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं थे जो उन्हें उन लोगों के बच्चों के साथ उचित प्रतिस्पर्धा में रखेगा जो उस नुकसान से पीड़ित नहीं थे। यदि ऐसा है, तो इसे उस परिभाषा का पालन करना चाहिए। 'राजनीतिक पीड़ित' न केवल ऐसे पीड़ितों के बच्चों को बाकी लोगों से अलग बनाता है, बल्कि इस तरह के

वर्गीकरण का नियमों के उद्देश्य के साथ एक उचित संबंध है जो सीटों के निष्पक्ष और न्यायसंगत वितरण के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है।

(दस) इसी तर्ज पर यह कहा जाना चाहिए कि राज्य के अधीन नियुक्ति चाहने वालों में से सर्वश्रेष्ठ और सबसे मेधावी लोगों का चयन किया जाना चाहिए, लेकिन यह भी उतना ही उचित और न्यायसंगत है कि पदों का एक उचित अनुपात उन लोगों को दिया जाना चाहिए, जो एक अजीब विकलांगता के कारण, उन लोगों के खिलाफ मौका नहीं दे सकते हैं जो इतने विकलांग नहीं हैं। यह अनुच्छेद 16(4) के सिद्धांत का उन लोगों के लिए विस्तार होगा जो अनुच्छेद 16(4) के तहत नहीं आते हैं। रक्षा कर्मी जो वर्षों से सेना, नौसेना और वायु सेना के साथ अपनी सेवा के कारण सरकारी सेवा में प्रवेश करने के अवसर खो चुके हैं और सामान्य नागरिक जीवन के साथ संपर्क भी खो चुके हैं, अनुशासन, बलिदान के गुणों के बावजूद, नागरिक नौकरियों के लिए नागरिकों के साथ प्रतिस्पर्धा करना बेहद मुश्किल हो सकता है। सार्वजनिक कर्तव्य, पहल, वफादारी और नेतृत्व की भावना जो उन्होंने निस्संदेह रक्षा बलों के सदस्यों के रूप में हासिल की होगी। राज्य का निस्संदेह यह दायित्व है कि वह उन भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार प्रदान करे जिन्होंने देश की सुरक्षा के हितों की निष्ठापूर्वक सेवा की है और अपने जीवन को जोखिम में डालने के लिए तैयार हैं। राज्य का दायित्व है कि वह उन्हें नागरिक आवेदकों की प्रतिस्पर्धा से बचाए, जिनके खिलाफ वे पहले से ही उल्लिखित कारणों के लिए मौका नहीं दे सकते हैं। इसलिए, राज्य द्वारा उन्हें भर्ती के स्रोत के रूप में अलग से वर्गीकृत करना और उनके लिए पद आरक्षित करना उचित है। न ही, यह कहा जा सकता

है कि सेवा की दक्षता प्रभावित होगी। भूतपूर्व सेवा कर्मियों के पास दूसरों के समान न्यूनतम योग्यताएं होनी चाहिए और वे अनुशासन, बलिदान, पहल, वफादारी, सार्वजनिक कर्तव्य की भावना आदि के गुणों से संपन्न होते हैं। और दक्षता का क्या मतलब है? जैसा कि न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर कहते हैं, "दक्षता का अर्थ है, अच्छी सरकार के संदर्भ में, केवल परीक्षा में अंक नहीं, बल्कि लोगों के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी सेवा।

(ग्यारह) इसलिए, हम भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में पदों के आरक्षण को बरकरार रखते हैं। हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस न्यायालय के एक विद्वान न्यायाधीश ने पहले ही दया राम बनाम हरियाणा राज्य के मामले में आरक्षण को बरकरार रखा है।

दोनों रिट याचिकाएं खारिज की जाती हैं। कोई कीमत नहीं।

न्यायमूर्ति एस सी मित्तल - मैं सहमत हूं।

न्यायमूर्ति सुरिंदर सिंह, - मैं भी सहमत हैं।

एन.के.एस.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

कोमल दहिया

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा